AMAR UJALA MY CITY Page 5

लखनऊ विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में एकरूपता के लिए जारी की गाइडलाइन

न्यूनतम 18 हजार रुपये प्रति सेमेस्टर हुई फीस

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में चलने वाले डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में एकरूपता लाने के लिए विवि प्रशासन ने इनमें दाखिले के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत डिप्लोमा पाठ्यक्त्रस्म दो कैटेगरी में चलेंगे। इनकी न्यूनतम फीस 18 हजार रुपए प्रति सेमेस्टर होगी। नई गाइडलाइन के हिसाब से विभागाध्यक्षों को उनके यहां संचालित पाठ्यक्त्रस्मों का आंकलन करना है। संचालित करने योग्य पाठ्यक्त्रस्मों का प्रस्ताव कुलसचिव को उपलब्ध कराना है। इसके बाद दाखिले के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।

विवि में अभी तक 40 से ज्यादा पाठ्यक्रम

डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं। इनमें कोई एकरूपता नहीं थी। स्व वित्तपोषित प्रणाली पर आधारित पाठ्यक्रमों की फीस एक-दूसरे से काफी अलग थी। इसको देखते हुए विवि कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्त्रस्मों के संचालन में काफी बदलाव किया जा रहा है। इन बदलावों को एकेडमिक काउंसिल सहित सभी समितियों से पास कराया जाएगा। पाठ्यक्त्रस्मों की फीस में होने बदलाव को वित्त समिति से पास कराया जा चुका है। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को उनके यहां के पाठ्यक्रमों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। विभागाध्यक्षों को गूगल फॉर्म पर यह ब्यौरा भेजना है। इससे काफी जल्द इनकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

डिप्लोमा के विद्यार्थी नहीं माने जाएंगे रेग्युलर

नई व्यवस्था में डिप्लोमा के विद्यार्थियों को अब रेग्युलर स्टूडेंट नहीं माना जाएगा। अभी तक उनको नियमित विद्यार्थी माना जाता है। ऐसे में वे छात्रसंघ चुनाव आदि भी लड़ सकते थे। नई व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा।

एक साल का ही होगा डिप्लोमा

लविवि ने साफ कर दिया है कि पाठ्यक्रमों की अवधि में एकरूपता होगी। इसके अनुसार अब डिप्लोमा पाठ्यक्त्रस्म दो सेमेस्टर यानी एक साल के होंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम 6 महीने के होंगे। इससे कम अवधि के पाठ्यक्त्रस्मों का संचालन कुलपति के अनुमोदन के बाद ही होगा।

एड ऑन की अनिवार्यता समाप्त, विभागाध्यक्ष करेंगे फैसला

लविवि ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संबंध में एडऑन की अनिवार्यता हटा ली है। अब डिप्लोमा पाठ्यक्त्रस्म में सीधे दाखिला लिया जा सकेगा। हालांकि विभागाध्यक्षों के ऊपर होगा कि वे चाहें तो संबंधित डिप्लोमा में यह शर्त शामिल रखें।

30 या उससे ज्यादा सीट वाले डिप्लोमा

- फीस न्यूनतम 18 हजार रुपये प्रति सेमेस्टर
- कोर्स संचालन के लिए कम से कम 20 दाखिले होना जरूरी

वन टाइम फीस	
इनरोलमेंट फीस	1000
एडमिशन फीस	1000
कॉशन मनी	2000
प्रति सेमेस्टर फीस	
ट्यूशन फीस	6000
डवलपमेंट फीस	5000
परीक्षा फीस	4000
स्थापना फीस	3000
लैब फीस	जरूरत पर
फील्ड विजिट	जरूरत पर

नोट : जिन पाठ्यक्रम में पहले से ही ज्यादा फीस होगी वहां फीस कम नहीं की जाएगी।

30 से कम सीट वाले डिप्लोमा और 10 सीट से कम पर पाठ्यक्रम नहीं होगा

- न्यूनतम 37 हजार रुपये प्रति सेमेस्टर
- कोर्स संचालन के लिए कम से कम 10 दाखिले होना जरूरी

वन टाइम फीस	
इनरोलमेंट फीस	1000
एडमिशन फीस	1000
कॉशन मनी	2000
प्रति सेमेस्टर फीस	
ट्यूशन फीस	12000
डवलपमेंट फीस	10000
परीक्षा फीस	4000
स्थापना फीस	8000
लैब फीस	न्यूनतम 3000
फील्ड विजिट	जरूरत पर

50 फीसदी विकास और 20 फीसदी ट्यूशन फीस लेगा विवि

लविवि ने इन पाठ्यक्रमों के लिए जो फीस निर्धारित की है उनमें विभाग और विवि प्रशासन का हिस्सा भी तय कर दिया गया है। इसके अनुसार परीक्षा, स्थापना, एनरोलमेंट और एडमिशन फीस लविवि के हिस्से में होगी जबकि विकास शुल्क में लविवि और विभाग बराबर के भागीदार होंगे। ट्यूशन फीस में विभाग का हिस्सा 80 और विवि का 20 फीसदी होगा।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम का भी होगा विकल्प

लविवि में अब ऑनलाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन का रास्ता भी खुल गया है। इसके अनुसार विभागाध्यक्षों को अपना प्रस्ताव देना है। एकेडमिक काउंसिल से पास कराकर इनको यूजीसी के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यूजीसी से अनुमोदन के बाद इनका संचालन शुरू हो जाएगा। नैक में ए प्लस वाले संस्थाओं को यूजीसी की अनुमति नहीं चाहिए होती है।

कॉरपोरेट, सरकारी कर्मचारी और सैन्यकर्मियों के लिए विकास शुल्क होगा अधिक

नई गाइडलाइन के अनुसार कॉरपोरेट, सरकारी कर्मचारी और सैन्यकर्मियों को अब पहले से अधिक फीस चुकानी होगी। अभी तक ये भी सामान्य विद्यार्थी के बराबर ही फीस चुकाते थे। नए नियम में 30 से ज्यादा सीट वाले पाठ्यक्रम में कॉरपोरेट, सरकारी कर्मचारी और सैन्यकर्मियों को विकास शुल्क के रूप में 19 हजार रुपये तथा 30 से कम सीट वाले पाठ्यक्रम में 30 हजार रुपये देना होगा। बाकी फीस सामान्य विद्यार्थियों वाली ही होगी।

HINDUSTAN Page 4 & 6

कॉलेजों में न तो शादियां होंगी न चलेंगी कोचिंग

लविवि प्रशासन

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

आदेश

- लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किए निर्देश
- कोर्ट के आदेश पर कॉलेजों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक

शहर के किसी भी सरकारी, एडेड और निजी कॉलेज में शादी समारोह या कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं हो सकेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी सहयुक्त महाविद्यालयों के परिसर के व्यवसायिक इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एक मामले में न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।

लविवि कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने सोमवार को ये निर्देश जारी किए हैं। कुलसचिव ने पत्र में लिखा है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शैक्षणिक संस्थानों के भवन/परिसर में होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों जैसे विवाह समारोह, कोचिंग सेंटरों के संचालन एवं दुकानों पर प्रतिबंधित है। इसलिए इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कॉलेज का मामला संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एलयू: बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है

संकेत

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

आगामी 29 जुलाई को प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (बीएड)-2020 की तिथि बढ़ाई जा सकती है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग की मौजूदगी में सोमवार को लविवि में हुई बैठक में इस पर मंथन किया गया।

कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश और परीक्षा केन्द्रों को लेकर किए जा रहे बदलावों के मद्देनजर इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसे 29 जुलाई को प्रदेश भर में 50 जिलों में कराने की तैयारी थी।

बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 कराने की जिम्मेदारी लविवि को सौंपी गई है। अभी तक पुराने निर्देशों के हिसाब से तैयारी की जा रही है। लविवि के कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों शासन ने स्ववित्तपोषित संस्थानों को परीक्षा केन्द्र न बनाने के निर्देश दिए हैं। अब सिर्फ राजकीय और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को ही केन्द्र बनाना है। इसके लिए दोबारा से प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत सभी राज्य विश्वविद्यालय को भी पत्र भेजे गए हैं। 8 जुलाई तक सभी से परीक्षा केन्द्र बनाने के लिए राजकीय और सहायता प्राप्त संस्थानों के नाम मांगे गए हैं। इसमें, जिला विद्यालय निरीक्षकों की भी मदद ली जा रही है। ऐसे में परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की पूरी संभावनाएं हैं।

लखनऊ विवि : केंद्रीकृत दाखिले के लिए 8 तक सहमति दे सकेंगे कॉलेज

लखनऊ। लखनऊ विवि की केंद्रीकृत दाखिला प्रणाली में शामिल होने के लिए अब महाविद्यालय 8 जुलाई तक अपनी सहमति भेज सकते हैं। विवि कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने सहमति भेजने की अंतिम तारीख 5 जुलाई से बढ़ाकर 8 जुलाई कर दी है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस साल से केंद्रीकृत दाखिले की व्यवस्था शुरू की है। इसमें शामिल होने के लिए महाविद्यालयों को काउंसलिंग फीस देनी होगी। प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की सूरत में यह फीस एक लाख रुपये तथा सामान्य पाठ्यक्रम के मामले में 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। योजना में शामिल होने के लिए कॉलेजों को पांच जुलाई तक अपनी सहमति देनी थी, जिसे बढाकर अब 8 जुलाई किया गया है। कॉलेज सिर्फ लविवि की प्रवेश प्रणाली पर ही आश्रित न रहें इसलिए उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने स्तर पर ही दाखिले लेते रहें। काउंसलिंग के समय कॉलेज जितनी सीट पर चाहेगा उतनी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगी।

लविवि की चित्रा येल विवि में पढ़ाएंगी हिंदी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय विभाग की चित्रा बाजपेयी ने अपने विभाग के साथ-साथ विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। चित्रा को अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में फुलब्राइट लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट के रूप में चयनित किया गया है। लविवि प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि चित्रा येल विवि में हिंदी पढ़ाएंगी। साथ ही चित्रा अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। फेलोशिप और आइवी लीग विश्वविद्यालय दोनों ही विश्व प्रसिद्ध और सम्मानित हैं।

NBT Page 5

फिर से तय होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के केंद्र

■ एनबीटी, लखनऊ : अपर मुख्य सचिव मोनिक गर्ग ने सोमवार को एलयू के प्रशासनिक अधिकारियों संग वीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर बैठक की। जिसमें एलयू को प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के निर्देश दिए गए। हालांकि परीक्षा स्थगित करने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि शासन के निर्देशानुसार अब सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में केंद्रों को लेकर फिर से तैयारी शुरू हो गई है।

एलयू बीएड समन्वयक अधिकारी ने सभी कॉलेजों व स्टेट यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर मांगी नई सूची

दोबारा बनेगी सूची

एलयू की तरफ से वीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों को लेकर सभी जिलों को पत्र जारी किया है। स्टेट यूनिवर्सिटी को भी पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है कि आठ जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की संशोधित सूची बनाकर भेज दी जाएं। शासनादेश के अनुसार नए केंद्रों में एडेड और सरकारी कॉलेजों को ही केंद्र बनाया जा सकता है।

आगे बढ़ सकती है तिथि

एलयू वीएड प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेई ने बताया कि 29 जुलाई को परीक्षा कराने के लिए तैयारियां हो चुकी थीं। शासनादेश के अनुसार नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें कुछ समय लग सकता है और परीक्षा की तारीख भी बढ़ानी पड़ सकती है। हालांकि इसका निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा।

एलयू कुलसचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पहले 1440 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होनी थीं। वहीं अब शासन ने सरकारी और एडेड कॉलेज को ही केंद्र बनाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में केंद्रों की संख्या कम भी हो सकती है। कुलसचिव ने बताया पहले परीक्षा 73 जनपदों में होनी थी, जिसे बाद में 50 कर दिया गया। हालांकि अब एक बार फिर प्रदेश के समस्त जनपदों में परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पहले एक केंद्र पर 300 अभ्यर्थियों की परीक्षा करवाने की तैयारी थी। केंद्र कम होने से अब यह संख्या 500 की जाएगी।

i-NEXT Page 4

दोबारा डिसाइड होंगे बीएड एग्जाम सेंटर

CONCEPT PIC

कोरोना के चलते परीक्षा नए सिरे से कराने की तैयारी

LUCKNOW (6 July) : कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष की बीएड प्रवेश परीक्षा में कई महत्वपूर्ण किए जा रहे हैं. इस बाबत अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने सोमवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक की. फिलहाल परीक्षा स्थगित करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. वहीं, शासन के आदेशानुसार अब सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाने के भी निर्देश आए हैं, जिसकी वजह से केंद्रों का फिर से निर्धारण किया जाएगा.

एलयू के पास है जिम्मा

बीएड प्रवेश परीक्षा का जिम्मा इस वर्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी को सौंपा गया है. लखनऊ यूनिवर्सिटी इसकी तैयारी कर रहा है. बीते दिनों शासन ने निर्देश जारी कर कहा कि किसी भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, हालांकि, यूनिवर्सिटी ने केंद्र को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली थी. अब नए निर्देश के अनुसार उसे फिर से कवायद करनी पड़ रही है. परीक्षा केंद्रों को लेकर सभी जिलों में एक पत्र जारी किया है. सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को भी पत्र भेजा गया है. इसमें लिखा है कि आठ जुलाई तक नए परीक्षा केंद्रों बनाएं, जिसमें एडेड और सरकारी कॉलेज ही शामिल करें. उसी अनुसार परीक्षा केंद्रों का चयन कर के सूची भी मांगी है.

आगे बढ़ सकती है परीक्षा की तिथि

एलयू वीएड प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेई ने बताया कि 29 जुलाई को परीक्षा कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी. अब नए सिरे से हमें तैयारियां करनी होंगी. इसमें समय लग सकता है. प्रवेश परीक्षा तिथि आगे खिसकने की भी संभावना है. हालांकि, इसका निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा. शासन के दिशा निर्देश के अनुसार हमारी कार्यप्रणाली रहेगी. एलयू कुलसचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पहले 1440 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होनी थी, अब सरकारी और एडेड कॉलेज को ही केंद्र बनाने से केंद्रों की संख्या में भी कमी हो सकती है.

सभी जिलों में होगी परीक्षा

कुलसचिव ने बताया पहले परीक्षा 73 जिलों में होनी थी, जिसे बाद में 50 कर दिया गया. अब परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में होगी. हां, केंद्रों की संख्या कम रहेगी. पहले 1440 केंद्र बनाए गए थे. एक केंद्र पर 300 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने की योजना थी. अब एक केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 500 की जा रही है.

एक सेंटर पर होंगे 500 स्टूडेंट्स.

DAINIK JAGRAN Page 5

फिर बनाए जाएंगे बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्र

जासं, लखनऊ : कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष की बीएड प्रवेश परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इस बाबत अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक की। इसमें लविवि को बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल परीक्षा स्थगित करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, शासन के आदेशानुसार अब सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाने के भी निर्देश आए हैं, जिसकी वजह से केंद्रों का फिर से निर्धारण किया जाएगा।

बीएड प्रवेश परीक्षा का जिम्मा इस वर्ष लविवि को सौंपा गया है। विवि इसकी तैयारी कर रहा है। बीते दिनों शासन ने निर्देश जारी कर कहा कि किसी भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। हालांकि, लविवि ने केंद्र को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। अब नए निर्देश के अनुसार कवायद करनी पड़ रही है। केंद्रों को लेकर सभी जिलों में एक पत्र जारी किया है। सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को भी पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है कि आठ जुलाई तक नए परीक्षा केंद्रों बनाएं, जिसमें एडेड और सरकारी कॉलेज ही शामिल करें। उसी अनुसार परीक्षा केंद्रों का चयन कर के सूची भी मांगी है। लविवि बीएड प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेई ने बताया कि 29 जुलाई को परीक्षा कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब नए सिरे से हमें तैयारियां करनी होंगी। इसमें समय लग सकता है। प्रवेश परीक्षा तिथि आगे खिसकने की भी संभावना है। हालांकि, इसका निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा। शासन के दिशा निर्देश के अनुसार हमारी कार्यप्रणाली रहेगी।

लविवि कुलसचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पहले 1440 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होनी थी, अब सरकारी और एडेड कॉलेज को ही केंद्र बनाने से केंद्रों की संख्या में भी कमी हो सकती है।

● सभी जिलों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र, एक केंद्र पर तीन सौ के बजाय पांच सौ अभ्यर्थी होंगे

सभी जनपदों में होगी परीक्षा

कुलसचिव ने बताया पहले परीक्षा 73 जिलों में होनी थी, जिसे बाद में 50 कर दिया गया। अब परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में होगी। हां, केंद्रों की संख्या कम रहेगी। पहले 1440 केंद्र बनाए गए थे। एक केंद्र पर 300 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने की योजना थी। अब एक केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 500 की जा रही है।

लविवि: शैक्षिक परिसर का नहीं होगा व्यावसायिक उपयोग

विवि प्रशासन ने कॉलेजों के व्यवसायिक प्रयोग पर रोक लगा दी है। सोमवार को एलयू कुलसचिव विनोद कुमार सिंह ने सभी राजकीय, आशासकीय सहायाता प्राप्त व स्वावित्तपोषित कॉलेजों भवन व परीसर के व्यवसायिक प्रयोग पर रोक लगा दी है। कुलसचिव ने पत्र में लिखा है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शैक्षणिक संस्थानों के भवन व परीसर में होने वाले व्यवसायिक गतिविधियों जैसे विवाह समारोह, कोचिंग सेंटोरो का संचालन एवं दुकानो पर प्रतिबंधित है।

विस्तृत खबर www.jagran.comपर पढ़ें।

PIONEER Page 3

दोबारा होगा बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों का निर्धारण

लखनऊ। शासन स्तर पर बीएड प्रवेश परीक्षा की मंजूरी मिलने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा के आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। 29 जुलाई को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर शासन के निर्देश पर एलयू ने बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों को लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर आठ जुलाई तक नए परीक्षा केंद्रों को लेकर सूची मांगी है। एलयू बीएड प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेई ने बताया कि 29 जुलाई को परीक्षा को लेकर सूची मांगी गई है। जिसमें राजकीय और एडेड कालेजों को शामिल करने को कहा गया है। सूची मिलने के बाद फिर से केंद्र निर्धारण किया जाएगा। वहीं एलयू कुलसचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पहले 1440 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होनी थीं लेकिन अब शासन की ओर से सरकारी और एडेड कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाने के आदेश जारी हुए हैं तो सम्भवत: परीक्षा केंद्रों में भी कमी हो सकती है।

TOI Page 2

All diploma courses to be of one-year duration, says LU

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: All the diploma courses offered by Lucknow University will now be of one year, while earlier the duration of some courses was two years. In order to bring uniformity in diploma and certificate courses offered by various departments, LU has drafted new guidelines for courses and sent them to all departments on Monday.

The diploma courses have been divided in two categories. In the first category, any certificate, diploma and PG diploma course with 30 or more seats will be allowed to run only if a minimum of 20 seats are filled. The fees for such courses will mandatorily be a minimum of Rs 18,000 per semester.

In case of specialized diploma, certificate and PG diplomas having less than 30 seats, the course will be allowed only if a minimum of 15 seats are filled. The minimum fees for these courses will be Rs 37,000 per semester.

And if the university gets University Grants Commission approval for running the course online, the minimum fees will be Rs 18,000 per semester and minimum seats will be 30.

However, the students pursuing diploma courses will not be counted as regular students, but will be given permission to use e-resources and reading room facility. The government employees, defence personnel and corporate-sponsored candidates taking admission in diploma courses will have to shell out more money than others.

The development fee, which is part of the total, will be Rs 19,000, significantly higher than Rs 4,000 for other candidates.